gathan, revived the exercise of discretionary powers and the present Chairman decided that the special dispensation admissions may continue in deserving cases by the Commissioner with the prior approval of the Chairman.

(d) The information is being compiled and will be laid on the table of the Sabha.

Request transfer of teachers of Kendriya Vidyalayas

343. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a published annual schedule of work relating to request-transfers of teachers of Kendriya Vidyalayas;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the reasons for not adhering thereto during the current and preceding sessions?

THE MINISTER OF HUMAN RE SOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. A tentative time schedule for the session 1990-91 for the request transfers of tea chers of Kendriya Vidyalayas was pre pared. The requests for transfers were to be invited in November, 1989 and trans fers were to be completed by 31-5-1990.

(c) The time schedule could not be adhered to on account of extension of receipt of requests upto 31-5-1990, incorporation of priorities in the computerised lists and the directions of the then Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan in April, 1991 to stop transfer in view of the general elections.

Request transfers of teachers of Kendriya Vidyalayas

344. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of HUMAN RE SOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sessional request transfers of teachers of Kendriya Vidyalayas ni respect of 1990-91 session are still going on even more than three months after expiry of the said session,

(b) if so, the reasons and the justification therefor, and

(c) by when the applications for the current session will be invited ?

THE MINISTER OF HUMAN RE SOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. Then then Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan ordered in April, 1991 that all transfers of teachers, Vice-Principals/ Principals including intra-regional ones be stopped in view of the general elections.

(c) In the context of the delay in processing the transfer applications already in hand, there is no decision to invite applications for the current session.

स्टेट बैंक आफ इन्दौर, चांदनी चौक, दिल्ली के महाप्रबन्धक के खिलाफ मामला

345. श्री राम नरेश यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर, चांदनी चौक, दिल्ली के अधिकारियों/महाप्रबन्धक ने जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके एक मृत व्यापारी के नाम पर लाखों रुपए निकाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उल्टे उपरोक्त व्यापारी की विधवा को परेशान किया जा रहा है ;

(घ) क्या बैंक के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई छानबीन करायी गयी है ;

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या विधवा के स्वर्गीय पति के नाम पर निकाली गई राशि को अब विधवा के परिवार के खाते में जमा किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Implementation of transfer orders regarding bank staff

346. DR. BAPU KALDATE:

SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

Will the Minister of FINANCE be pleased *to* state:

(a) what is the number of status-quo orders relating to transfer of staff received by the Branches of Associate Banks of the State Bank of India situated at Chand ni Chowk, Delhi, issued by the Assistant Labour Commissioner (Central),Dalhousie Road, New Delhi during 1st June, 1985 to 15th June, 1985 with details, bankwise and branch-wise;

(b) whether these status-quo orders were implemented; if not, the reasons therefor stating the action taken by Government against Bank Management for non-compliance the status-quo orders;

(c) whether it is a fact that transfer orders were effected even after receiving the status-quo orders issued by the Assistant Labour Commissioner; and

(d) if so, what action has been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) *to* (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

हरिजनों पर अत्याचार

347. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिजनों एवं आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) वर्षवार एवं राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनायें हुई हैं तथा इन घटनाओं में मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है ; और

(घ) हरिजनों तथा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	अनुसूचित जातियों	अनुसूचित जनजातियों
	के विरुद्ध	अपराध
1988	15,207	3,364
1989	15,799	3,623
1990	16,810	3,572

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार करने के कारण अनेक रहे हैं, जैसे-भूमि विवाद, कानूनी न्यूनतम मजदूरी की मांग, बंधवा मजदूर अथवा जबरन मजदूरी प्रथा प्रतिरोध, अस्पृश्यता की प्रथा का विरोध, शिक्षा के माध्यम से उत्पन्न जागरूकता के कारण समान अधिकारों के दावे, अपनी महिलाओं के सम्मान की रक्षा के प्रयास आदि ।